भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1030
25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कम वजन वाले शिशुओं के जन्म की उच्च दर

†1030. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देशभर में कम वजन वाले शिशुओं के जन्म की उच्च दर के समाधान के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष उपाय किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले एक दशक में देश में कम वजन वाले शिशुओं के जन्म की उच्च दर को कम करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और कुछ क्षेत्रों में इस समस्या के बने रहने में किन कारकों ने योगदान दिया है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं कि गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से सामाजिक- आर्थिक रूप से वंचित समूहों की महिलाओं को कम वजन वाले शिशुओं के जन्म के जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त पोषण और प्रसवपूर्व देखभाल उपलब्ध हो और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास कम वजन वाले शिशुओं के जन्म की व्यापकता में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की कोई योजना है, जहाँ पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में मिजोरम और नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में यह व्यापकता अधिक है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार विशेषकर से कम वजन वाले शिशुओं के जन्म की व्यापकता वाले क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेपों को लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क), (घ) और (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कम वजन वाले शिशुओं के जन्म की व्यापकता को दूर करने के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित निम्नलिखित कार्यकलापों को क्रियान्वित किया जाता है:

- प्रसवपूर्व देखभाल मातृ स्वास्थ्य कार्यकलापों का एक प्रमुख घटक है, जिसमें प्रारंभिक गर्भावस्था पंजीकरण, चार प्रसवपूर्व जाँचें और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के अंतर्गत उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का प्रबंधन शामिल है।
- इसके अतिरिक्त, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों (वीएचएनडी) के दौरान अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता मातृ पोषण और स्वास्थ्य प्रथाओं पर परामर्श प्रदान करते हैं और कम वज़न वाले शिशुओं

के जन्म के जोखिम को कम करने के लिए समुदाय में व्यवहार परिवर्तन संचार की सुविधा भी प्रदान करते हैं।

- माताओं में एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के माध्यम से आयरन और फोलिक एसिड (आईएफए) की खुराक प्रदान की जाती है।
- प्रसवोत्तर क्रियाकलाप नवजात शिशुओं, विशेष रूप से कम वज़न वाले या समय से पहले जन्मे शिशुओं की देखभाल पर केंद्रित होते हैं। सुविधाकेंद्र-आधारित नवजात शिशु देखभाल (एफबीएनसी) मातृ नवजात शिशु देखभाल इकाइयों (एमएनसीयू), विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों (एसएनसीयू) और नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाइयों (एनबीएसयू) के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिनके माध्यम से छोटे और बीमार नवजात शिशुओं को विशेष देखभाल प्रदान की जाती हैं।
- कंगारू मदर केयर (केएमसी), गृह-आधारित नवजात शिशु देखभाल (एचबीएनसी), गृह-आधारित बाल शिशु देखभाल (एचबीवाईसी) और मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन (एमएए) जैसे कार्यक्रमगत कार्यकलाप कम वजन (एलबीडब्ल्यू) वाले शिशुओं के जीवित रहने और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करते हैं।
- एनएचएम, सेवा वितरण में प्रभावी कार्यान्वयन और समानता के लिए वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है।
- कार्यक्रम कार्यान्वयन में सुधार के लिए स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु आवधिक क्षेत्र दौरे, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मध्यावधि समीक्षा बैठकें और सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) प्रमुख कार्यकलाप हैं।

(ख): राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में कम वज़न वाले बच्चों के जन्म के मामलों में गिरावट देखी गई है, जो एनएफएचएस-3 (2005-06) में 21.5% से घटकर एनएफएचएस-5 (2019-21) में 18.2% हो गई है। देश में कम वज़न वाले बच्चों के जन्म के प्रमुख कारण सामाजिक-आर्थिक असमानताएं और मातृ चिकित्सा स्थितियों सहित विभिन्न कारक हैं।

(ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं कि सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों सहित सभी गर्भवती महिलाओं को देश भर में कम वजन वाले शिशुओं के जन्म के जोखिम को कम करने के लिए मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत प्रसवपूर्व देखभाल सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो, जो नीचे दिए गए हैं: -

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) जन स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन सहित, पूर्णतः निःशुल्क और कोई खर्च किए बिना प्रसव का अधिकार देता है। इन अधिकारों में निःशुल्क दवाएँ, उपभोग्य वस्तुएँ, प्रवास के दौरान निःशुल्क

आहार, निःशुल्क निदान, निःशुल्क परिवहन और आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क रक्ताधान शामिल हैं। एक वर्ष तक की आयु के रोगी शिशुओं के लिए भी इसी प्रकार के अधिकार उपलब्ध हैं।

- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए माँग संवर्धन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।
- विशेष रूप से आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में सुधार के लिए आउटरीच शिविरों का प्रावधान किया जाता है। इस मंच का उपयोग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सामुदायिक जुटाव के साथ-साथ उच्च जोखिम वाले गर्भधारण पर नज़र रखने के लिए किया जाता है।
- गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, गर्भावस्था के खतरे के संकेतों, लाभकारी योजनाओं और संस्थागत प्रसव के बारे में शिक्षित करने के लिए मातृ एवं शिशु सुरक्षा (एमसीपी) कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका वितरित की जाती है।
- एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यक्रम छह लाभार्थी आयु समूहों - बच्चों (6-59 महीने), बच्चों (5 -9 वर्ष), किशोरों (10-19 वर्ष), गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और प्रजनन आयु समूह (15-49 वर्ष) की महिलाओं में संस्थागत तंत्र के माध्यम से छह कार्यकलापों के कार्यान्वयन के माध्यम से एनीमिया को कम करने के लिए कार्यान्वित किया गया है।
- मंत्रालय गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पूरक पोषण प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के साथ समन्वय भी करता है ताकि मातृ कुपोषण को दूर किया जा सके और पोषण अभियान के तहत स्वस्थ गर्भावस्था के परिणामों को बढ़ावा दिया जा सके।

*****